

‘चाहे आप रिटायर हो जाएं या घर बैठ जाएं, हम आपको बख्शेंगे नहीं’

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को सार्वजनिक धमकी दी

-रेणु मिश्र-

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1, अगस्त। एक तीखे बयान में, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह भाजपा के लिए वोट चुरा रहा है।

इसे देशद्रोह करार देते हुए, राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई जांच और सामने आए खुलासे एक “परमाणु बम” की तरह फटेंगे और इन धमकों के असर में चुनाव आयोग कहीं भी दिखाई नहीं देगा।

इसी के साथ, उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह चेतावनी जारी की कि चुनाव आयोग में ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी भाजपा के लिए वोट चोरी में शामिल पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह देश के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के समान है। उन्होंने कहा, “आप कहीं भी हों, सेवानिवृत्त हों या न हों, हम आपको दूढ़ निकालेंगे।”

■ राहुल ने कहा, आपने मतदाता सूचियों से नाम काटने का अगर काम किया है तो वह देशद्रोह के समान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता।

■ राहुल ने इस संदर्भ में आगे कहा कि “वोटों की चोरी” को पकड़ने में चुनाव आयोग ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया, अतः हमने हमारे साधनों से गत छः महीने में जाँच की है, वोटों की चोरी के प्रकरण की तथा जो जानकारी हमें मिली है, वह विस्फोटक है, “एटम बम” की तरह, और वह धमका चुनाव आयोग को खत्म कर देगा।

■ राहुल ने कहा कि यह विस्फोटक जानकारी पूरी तरह संजोकर, एक सप्ताह में अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान उजागर करेंगे।

■ चुनाव आयोग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी के आरोप आधारहीन व गैरजिम्मेदाराना हैं। अतः चुनाव आयोग के अधिकारी राहुल गांधी के वक्तव्य को तवज्जो नहीं दें तथा जायज़ व पारदर्शी तरीके से अपना काम करते रहें।

विपक्ष के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी को शुरू में मध्य प्रदेश में संदेह हुआ था, और महाराष्ट्र में यह और पुष्टा

आयोग ने हमारा समर्थन या सहयोग नहीं किया, इसलिए हमने खुद के स्तर पर जाँच की। जो हमें मिला, वह एक परमाणु बम की तरह है; एक बार जब यह फट जाएगा, तो चुनाव आयोग कहीं भी दिखाई नहीं देगा।”

गांधी ने कहा कि पार्टी ने गहराई और बारीकी से जाँच की। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को पूरे विस्तृत विवरण तक पहुँचने में लगभग छह महीने लगे, और निष्कर्षों का खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग किस तरह भाजपा के पक्ष में वोटों का हेरफेर कर रहा है।

इस तरह के तीखे हमले के बाद, बचाव की मुद्रा में आए चुनाव आयोग के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को “आधारहीन” और “गैर-जिम्मेदाराना” कहकर खारिज कर दिया। आयोग ने एक बयान में कहा, “दैनिक धमकियों और आधारहीन आरोपों के बावजूद, आयोग सभी चुनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘एसटी वर्ग की बेटियों को समान अधिकार से वंचित रखना अनुचित’

जयपुर, 1 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसटी वर्ग की महिला के पैतृक संपत्ति में अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि आजादी के सात दशक बाद भी एसटी समुदाय की बेटियों को समान अधिकारों से वंचित करना अनुचित है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत सरकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के प्रावधानों की समीक्षा करे

■ हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से, जरूरत हो तो कानून में संशोधन करने को कहा।

और यदि जरूरत हो तो प्रावधानों में संशोधन करे। अदालत ने आशा जताई है कि केन्द्र सरकार इस मामले में विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमला नेती के मामले में निर्देश के आधार पर उचित निर्णय लेगी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने ये आदेश मंत्री देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वहीं, अदालत ने याचिकाकर्ता से जुड़े मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश अर्जों को खारिज करते हुए एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि वे दो साल में लॉबिड वाद का निस्तारण करें।

अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अन्य देशों को अब अमेरिका की महँगाई का भार वहन करना पड़ेगा’

ट्रंप का दावा काफी गलत साबित हुआ
टैरिफ बढ़ाने के बारे में

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वॉशिंगटन, 1 अगस्त। अमेरिका में 1 अगस्त का दिन है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नए शुल्क प्रभावी हो रहे हैं, ऐसे में अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक नई सच्चाई से हतप्रभ नज़र आ रहा है।

शेयरों में व्यापक गिरावट आई है और नए आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है।

अभी जारी किए गए जुलाई के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में केवल 73,000 नई नौकरियाँ जोड़ी गईं, जो अब तक की सबसे कम हैं। नई नौकरियों का सुजन, जो अर्थव्यवस्था की गति का एक प्रमुख पैमाना है, कुछ हद तक धीमा हो रहा था और अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं।

अमेरिका आमूलचूल परिवर्तन की नई वास्तविकता के प्रति जाग रहा है। एक मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार का गढ़ रहा अमेरिका अब एक संरक्षणवादी (प्रोटैक्शनिस्ट)

■ अमेरिकावासियों को अब महँगी पड़ने लगीं वो वस्तुएँ, जो वो सदा से आसानी से सस्ते दामों में खरीदने के आदी हो गये थे।

■ उदाहरण के लिए, फ्रांस व जर्मनी की वाइन्स व स्विटज़रलैंड की लम्जरी घड़ियाँ।

■ अमेरिका की इकॉनमी भी “स्लोडाउन” के दौर में फँसती जा रही है। उदाहरण के लिए, जुलाई माह के आंकड़ों के अनुसार, केवल 73,000 नये रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जो कई दशकों में सबसे कम है।

■ भारत में निर्मित सामान लगभग गायब ही हो जाएगा, अमेरिका के मार्केट में। क्योंकि 25 प्रतिशत का टैरिफ व ऊपर से रूस से ऑयल खरीदने के कारण लगी पेनल्टी के कारण भारत का माल अन्य देशों की तुलना में महँगा हो जायेगा।

अर्थव्यवस्था की ओर रुख कर रहा है। इसने न केवल अमेरिका के करीबी सहयोगियों को निराश किया है, बल्कि आम अमेरिकियों को भी निराश कर रहा है।

देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी, के विपरीत यह एहसास हो रहा है कि अमेरिका के लोगों को उन कई उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करना होगा, जिनकी उन्हें आदत है। बेशक, इस मार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोमवार, बुधवार व गुरुवार को “इन्टर्न्स एंट्री” वर्जित होगी सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट में यह नई व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आग्रह पर की गई है

-जाल खंभाता-

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कानून के इन्टर्न्स को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम में प्रवेश से रोक दिया है, जो कि विविध मामलों की सुनवाई के दिन होते हैं।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध के बाद उठाया गया है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया, “सक्षम अधिकारियों ने विविध प्रकार के केसों की सुनवाई के दिनों में, यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कानून के इन्टर्न्स के कोर्टरूम के अंदर प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध

■ वरिष्ठ व प्रैक्टिसिंग वकीलों की शिकायत थी कि “इन्टर्न्स” की भारी भीड़ के कारण वकीलों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने में भी दिक्कत हो रही थी।

■ साथ ही इन प्रशिक्षु इन्टर्न्स की उपस्थिति के कारण न्यायालय में सभी सीटों भर जाती थीं तथा इन्टर्न्स आग्रह करने के बाद भी इन सीटों को खाली करने को तैयार नहीं होते थे तथा प्रैक्टिसिंग वकीलों को काफी समय खड़ा रहना पड़ता था।

को स्वीकार कर लिया है।” कानून के इन्टर्न्स को नियमित सुनवाई के दिनों, यानी बुधवार और गुरुवार को कोर्ट परिसर और गलियारों में जाने की अनुमति होगी। बार एसोसिएशन ने पहले भी कोर्ट को एक पत्र लिखकर कानून के इन्टर्न्स

पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था, जिसमें कोर्ट के अंदर भीड़भाड़ का हवाला दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था, “यह देखा गया है कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अरुण चतुर्वेदी
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने



अरुण चतुर्वेदी

जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने बड़ी

■ आने वाले दिनों में और राजनैतिक नियुक्तियों होने की संभावना है।

राजनीतिक नियुक्ति की है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है।

अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही और राजनैतिक नियुक्तियाँ होने की संभावना है। इसमें प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होने की संभावना है।

1974 से चला आ रहा, 75 बीघा जमीन की अवाप्ति का मामला अब निपटा

अदालत ने जे.एल.एन. मार्ग पर स्थित उक्त भूमि पर मूल पक्षकार के वंशजों का दावा खारिज किया और कहा कि राज्य सरकार ही भूमि का मालिकाना हक रखती है

■ मूल पक्षकार के वंशजों को 1990 में सिविल जज ने राहत देते हुए आदेश दिये थे कि राज्य सरकार उक्त भूमि अवाप्त किये जाने की एवज में पक्षकारों को प्रति बीघा 40,000 रुपये तथा 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति और 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करे।

■ अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर उक्त आदेश को रद्द कर दिया और यह भी आदेश दिए हैं कि यदि उक्त भूमि को अवाप्त करने और कब्जा लेने की प्रक्रिया में कोई आड़े आता है तो राज्य सरकार उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकती है।

रु. प्रति बीघा पर किराये पर दी थी।

इस मामले के जिरह के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि बृजमोहन के निधन के बाद 1, नवम्बर, 1958 को सरकार ने सार्वजनिक कार्यों के लिए ले लिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में मूल पक्षकार त्रिलोकी नाथ साहनी ने 1960 में राजस्व के विभाग के सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष उक्त भूमि के सवाईचक घोषित किये जाने के खिलाफ आवेदन दायर किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि तहसीलदार ने

त्रिलोकीनाथ को घुसपैठिए नहीं मानते हुए, और माफीदार के पट्टे के साथ एक उक्त जमीन पर किरायेदार घोषित कर दिया, हालाँकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को राज्य सरकार के अपील पर खारिज कर दिया था, और अपीलेट अदालतों ने भी कलेक्टर के आदेश को सही माना।

विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि वर्ष 1979 में हाईकोर्ट की एक खण्डपीठ ने आदेश पारित करे जिसके तहत सरकार को आदेश दिये गये थे, कि त्रिलोकीनाथ जिस भूमि के कब्जे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निर्णय ली। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रह नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं और वह याचिका में की गई प्रार्थना से भी आगे बढ़कर फैसला दे सकता है। एसओजी की रिपोर्ट मिलने के स्रोत नहीं बताते की राज्य सरकार की आपत्ति पर याचिकाकर्ता ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दस्तावेज कहाँ से मिले, वे सही हैं या नहीं, यह महत्व रखता है। यदि दस्तावेज सही हैं तो हाईकोर्ट को जर्नलित में उन पर संज्ञान लेना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी करने के बाद, अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।

■ याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अपनी बहस पूरी की।

विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

हम देश के नागरिक यह स्वीकार नहीं करेंगे कि विदेशी फर्जी मतदाता, भारत के भाग्य विधाता बनें (भाग-2)

पूर्व में दिनांक 25 जुलाई 2025 के राष्ट्रदूत के अंक में उपरोक्त शीर्षक से एक सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ। वर्तमान लेख उस लेख का दूसरा भाग है।

पूर्व के लेख में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि विशेष सघन निरीक्षण को कार्यवाही में चुनाव आयोग ने यह पाया है कि बिहार की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 66 लाख मतदाताओं ने 22 लाख वे लोग हैं जो मृतक हैं, 36 लाख वे हैं जो अन्य स्थायी स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं अथवा जिसका कोई अता पता नहीं है। एक लाख ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अन्तिम तिथि तक अपने फार्म भरकर वापिस नहीं किये गये हैं। हाँ इनकी वास्तविक संख्या का पता 1 अगस्त 2025 के बाद स्कूटनी समाप्ति पर पता चलेगा। यह भी सच है कि वास्तविक (उहलहा) मतदाता के नाम 1 अगस्त 2025 से 1 सितम्बर 2025 के मध्य, जोड़े भी जा सकते हैं। 7 लाख मतदाता को Multiple Places पर पंजीकृत हैं, उन्हें केवल एक स्थान पर रखा जावेगा।

ये रिट् याचिकायें कई व्यक्तियों अथवा संस्थाओं आदि ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की हैं जो जेरकार हैं। मुख्य याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिवव रिफोर्म की है जिसमें प्रशान्त भूषण सीनियर एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं। देश के सभी पर्याप्त एडवोकेट इन याचिकाओं में विभिन्न याचिकाओं में पैरवी कर रहे हैं जिनमें मुख्य सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी एक हैं। चुनाव आयोग की ओर से पैरवी करने वालों में सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी हैं।

जवाब व बहस के दौरान चुनाव आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य की मतदाता सूची का विशेष सघन निरीक्षण की प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत् की जा रही है जो प्रक्रिया विधि सम्मत है। दिनांक 28 जुलाई 2025 की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के समय कहा कि अघार कार्ड व ईपीआईसी कार्ड पुनरीक्षण के समय देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनके बाबत यह धारणा बनाने का अधिकार है कि वे सही हैं। दिनांक 28 जुलाई 2025 को खण्डपीठ ने स्थान आदेश देने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ था कि चुनाव आयोग 1 अगस्त 2025 तक अपनी ड्राफ्ट Electoral Roll अपनी यथोन्निश्चित तारीख तक प्रकाशित कर सकते हैं।

दिनांक 28 जुलाई 2025 की केस की तारीख दिनांक 29 जुलाई, 2025 को कुछ दूर सुनवाई के बाद स्थगित कर दी गई, क्योंकि खण्डपीठ के सदस्य जस्टिस सूर्यकान्त उस दिन एक अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त थे। खण्डपीठ के दूसरे न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची हैं। दिनांक 28.07.2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मसोदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह चुनाव आयोग की विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बार में अन्तिम निर्णय करेगा।

दिनांक 28.07.2025 की सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने दो मुख्य सुझाव दिये वे इस प्रकार हैं:-

(1) जस्टिस सूर्यकान्त ने सुझाव दिया कि व्यापक रूप से निष्कासन के बजाय व्यापक रूप से समावेश की दिशा में काम होना चाहिये।

(2) खण्डपीठ ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वह बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत् आधार व वोटर आई स्वीकार करना जारी रखे। कोर्ट ने कहा जहां तक राशन कार्ड की बात है वे आसानी से नकली बनाये जा सकते हैं। यह भी कहा गया कि कोई भी डोक्यूमेण्ट फर्जी बनाया जा सकता है।

दिनांक 29 जुलाई, 2025 की बहस भी बहुत रोचक रही।

एडीआर के एडवोकेट ने चुनाव आयोग के एडवोकेट के उस स्टेटेमेंट की ओर खण्डपीठ का ध्यान आकर्षित किया कि जब 65 लाख मतदाताओं ने जब फार्म ही नहीं भरा, क्योंकि वे या तो स्वर्गवासी हो गये अथवा कहीं चले गये तो क्या उन तथाकथित लोगों को पुनः अपना नाम लिस्ट में दाखिल कराने के हेतु कार्यवाही करनी होगी। खण्डपीठ के न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है अतः उसकी

यह सच है कि चुनाव आयोग को नागरिकता के निर्णय का अधिकार नहीं है और न वह स्वयं यह मानता है, किन्तु उसे यह देखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है, वह भारत का नागरिक है या नहीं और वह वही डोक्यूमेन्ट मांग रहा है जो नागरिकता के लिये आवश्यक है।

खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद 12-13 अगस्त 2025 की तारीख अन्तिम सुनवाई के लिये नियत कर दी। इस प्रकार इस प्रसंग में दिनांक 12-13 अगस्त 2025 को बहस होगी। इन दिनों दोनों पक्षों के सीनियर एडवोकेट्स ने जो बहस की, जो आपत्तियाँ उठाई तथा जो विशेष आपत्तियाँ रिट् याचिकाओं तथा चुनाव आयोग ने उठाई हैं, हम यदि मंथन करें तो निम्नलिखित Issues पर बहस हो सकती है:-

(1) चूँकि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकर केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है और जो व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 5(क) के अनुसार भारत में जन्मा था, (ख) जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा था या (ग) भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है तथा जो प्रारम्भ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में साधारण तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा और अनुच्छेद 6 से 11 के अनुसार जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, वही व्यक्ति मतदान कर सकता है। इस प्रकार नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोग जो वहां के निवासी हैं मतदान के अधिकारी नहीं हैं। इस आधार पर उनके डोमीसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड व राशन कार्ड जो उन्होंने प्राप्त किये हैं वे फर्जी हैं।

(2) सुप्रीम कोर्ट अथवा हाईकोर्ट में वही व्यक्ति रिट् याचिका दायर कर सकता है जो भारत का नागरिक है और जिसे संविधान के चेप्टर -III के अधिकार हैं जो याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं पीआईएल हैं और ऐसे व्यक्तियों की ओर से हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं अथवा जीवित ही नहीं हैं अथवा अन्य राज्यों में चले गये हैं यानी इनका सम्बन्ध चेप्टर -III के अधिकारों से नहीं है।

(3) चूँकि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसे Electoral Roll के बाबत अग्रोक्षण निर्देशन और निरीक्षण के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं अतः ऐसी संस्था के विरुद्ध रिट् याचिकायें जो आधार याचिकाओं में दिये हैं, उनके बाबत हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, क्योंकि Electoral का विषय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार है।

(4) चुनाव आयोग ने इस विषय को काफी गंभीर माना है। उसका मानना है कि यदि उसके अधिकारियों ने विशेष सघन निरीक्षण की कार्यवाही में नाम मतदाता सूची से हटा दिया है वह नागरिक मतदाता है, उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व नियमों के अनुसार अपील का अधिकार है।

(5) आधार कार्ड व राशनकार्ड आदि पब्लिक डोक्यूमेन्ट्स हैं तो भी ये नागरिकता साबित करने के हेतु सारभूत व रेलेवेन्ट नहीं है।

(6) बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं अतः यह वाद विषय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में शोभाशित निर्णित होना आवश्यक है। विषय गम्भीर है अतः इस केस को संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णित किये जाने के बाबत भी विचार होना आवश्यक है।

(7) यह सच है कि चुनाव आयोग को नागरिकता के निर्णय का अधिकार नहीं है और न वह स्वयं यह मानता है, किन्तु उसे यह देखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है, वह भारत का नागरिक है या नहीं और वह वही डोक्यूमेन्ट मांग रहा है जो नागरिकता के लिये आवश्यक है।

दिनांक 01.08.2025 को चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता पुनरीक्षण अभियान की पहली ड्रफ्ट लिस्ट जारी की है। इसे अपने अधिकारिक वेबसाइट पर सांय 3 बजे अपलोड किया गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों को इसकी कॉपी भेजी गई है। इस लिस्ट में नये नाम जोड़े गये हैं। लोगों के नाम काटे भी गये हैं। 20 लाख से अधिक के नाम काटे गये हैं, जिन्हें मृत होना पाया गया है।

चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि सभी ऐसे लोग अथवा उसने परिवार जन, जिनके नाम नहीं हैं वे फार्म भरकर बीएलओ अथवा सम्मक्ष अधिकारी को भेज दें, कानूनानुसार सुनवाई कर जाँच की जावेगी और यदि उन्हें मतदान का अधिकारी पाया गया तो उनका नाम जोड़ दिये जावेगें। 1 सितम्बर 2025 तक संशोधन कराने का अवसर दिया है। 8 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम दो जगह पर हैं, उन्हें एक जगह वोट देने का अधिकार होगा। कई ऐसे लोग हैं, जो अपना गांव (स्थान) छोड़कर चले गये हैं। कई लाख ऐसे हैं जो बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिक हैं। जाँच का काम जारी है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन,

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



सुनील दत्त गोयल

जब डोनाल्ड ट्रम्प ने 'राष्ट्रीय आपातकाल' का हवाला देते हुए भारतीय निर्यात पर 25-26 प्रतिशत टैरिफ लगाया, तो प्रतिक्रिया तेज थी: बाजारों में अफरा-तफरी मच गई, निर्यातकों ने राहत की माँग की, और टिप्पणीकारों ने भारत को हाशिये पर बता दिया। लेकिन टैरिफ अस्तित्व का खतरा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था—जो 80 प्रतिशत घरेलू माँग पर निर्भर है—सालाना निर्यात घाटे में 7 अरब डॉलर का नुकसान झेल सकती है। असली खतरा इस बात में है कि भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। अगर वह दबाव में ढिलाई भरतता है, तो इसके परिणाम व्यापार से कहीं आगे तक जाएँ। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स (\$2.1 अरब निर्यात, 27 प्रतिशत अमेरिका को) को 4-5 प्रतिशत मार्जिन का नुकसान हो रहा है।

अगर हारे पर छूट खत्म हो जाती

शिक्षक बने पर्यावरण प्रहरी: बूंदी के मंडावरा के सरकारी स्कूल में नवाचार से सूरत बदली

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडावरा के शिक्षकों ने अपने प्रयास और जन भागीदारी से एक ऊबड़-खाबड़ टीले को सुरम्य और हरे-भरे मरु उद्यान में बदल दिया है

अनुप्रिया

जब राष्ट्र निर्माताओं का संकल्प और जुनून सरकार की प्रतिबद्धता और जवाबदेहिता से मिलता है तो सुशासन की छाया में बंजर जमीन भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पैदल मां के नाम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान की प्रतिबद्धता को बूंदी जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडावरा के कर्मयोगी शिक्षकों ने धरातल पर साकार कर दिया है। इन शिक्षकों ने अपने भागीरथी प्रयास और जन-भागीदारी की शक्ति से एक ऊबड़-खाबड़ टीले को सुरम्य और हरे-भरे मरुस्थान में बदल दिया है, जो आज पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा-पुंज बन गया है।

संकल्प से सृजन की यात्रा-

विद्यालय में अभियान से पूर्व की फोटो।

भेरूपुरा बरड़ पंचायत के गाँव मंडावरा स्थित यह विद्यालय कुछ वर्ष पूर्व तक एक साधारण टीले पर बना था। प्रधानाचार्य किशन लाल मीणा और शिक्षक गोपाल मीणा की दूरदर्शी सोच ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का बीड़ा उठाया और एक सुनियोजित योजना के साथ इस ज्ञान के मंदिर का कायाकल्प शुरू हुआ। मिट्टी डालकर भूमि को समतल किया गया, पक्की दीवारें बनाकर परिसर को सीढ़ीनुमा स्वरूप दिया और फिर शुरू हुआ हरियाली का मिशन।

नवाचार और सहभागिता का संगम—इस हरित क्रांति में केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि विद्यार्थी और ग्रामवासी भी सक्रिय भागीदार बनें।

विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाने के लिए 'पौधे गोद लेने' की अनूठी परंपरा शुरू की गई, जहाँ हर विद्यार्थी अपने गोद लिए पौधे की सुरक्षा करता है, उसे पानी देता है। विद्यालय में एक बीज बैंक स्थापित किया गया है जो न केवल स्कूल की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि ग्रामीणों और आस-पास के अन्य विद्यालयों को भी निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को विस्तार दे रहा है। ग्रामवासी स्वेच्छा से पौधों की देखभाल और सिंचाई की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में विद्यालय परिसर में अपराजिता, पारिजात और मधु कामिनी जैसे सुगंधित फूलों के

अभियान के बाद की फोटो, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि जन भागीदारी और जुनून ने कैसे इस अभियान को पूर्ण सफल बनाया है।

साथ-साथ अनेक फलदार और छायादार वृक्ष लहलहा रहे हैं, जो हर किसी को आकर्षित करते हैं।

सिर्फ हरियाली नहीं, समग्र विकास का मॉडल—जब शिक्षकों ने अपना समय और श्रम दिया तो गांव का माहौल बदल गया। सामुदायिक भागीदारी ने नया आकार लिया, पौधारोपण और रखरखाव में स्थानीय आवश्यकता और भौगोलिक मापदंड के हिसाब से नीति बनाई गई, फिजिकल ऑडिट शुरू हुई, पारदर्शिता मानक मूल्य बन गया। आर्थिक सहयोग के एक-एक पैसे का हिसाब रखा जाने लगा जिससे भागीदारों को उत्साह मिला।

स्थानीय समुदाय में इस बगीचे

और विद्यालय के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी जिससे शैक्षणिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ।

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ यह विद्यालय शैक्षिक और भौतिक विकास के हर मानदंड पर खरा उतरता है। बंदरों से बचाव के लिए वायर फेंसिंग, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ और वाटर कुलर, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय और दूधिया रोशनी में वॉलीबॉल खेलने की सुविधा वाला खेल मैदान इसे एक आदर्श विद्यालय बनाते हैं।

अनुप्रिया, पीआरओ, बूंदी।

बीकानेर में 11 जर्जर स्कूल दूसरे स्कूल में शिफ्ट होंगे

बीकानेर में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने स्कूलों का सर्वे किया

बीकानेर, (निसं)। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जर्जर और जीर्ण-शोध सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुरक्षित भवन तलाशे जा रहे हैं। बीकानेर जिले में 11 स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई अब पास के ही दूसरे स्कूलों में होगी।

झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद शिक्षा विभाग की ओर से राज्यभर में

जर्जर स्कूलों का सर्वे करवाया जा रहा है। बीकानेर में भी शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने अनेक स्कूलों का सर्वे किया है। सर्वे में 11 स्कूल ऐसे सामने आए हैं जहां स्कूल भवन स्थिति खराब है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन स्कूलों को पास के स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। मुक्ता प्रसाद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम नगर

को मुक्ता प्रसाद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट किया गया है। यहां अब एक भवन में तीन स्कूलों का संचालन हो रहा है।

पहली पारी में सुबह 7 से 12.30 माहतामा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मुक्ता प्रसाद के 350 विद्यार्थियों को कक्षाएं लगाई जा रही हैं। जबकि सेकंड पारी में स्कूल के पांच कमरों में दोपहर 12.30 से 6

बजे तक भीम नगर स्कूल के 250 तथा चार कमरों में राउप्रावि वाई नंबर 17 के 137 बच्चों की कक्षाएं लग रही हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवनपुरी दक्षिण विस्तार में भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंबेडकर कॉलोनी और राउप्रावि पवनपुरी को शिफ्ट किया जाएगा। बीकानेर जिले में करीब 32 सरकारी स्कूल किराए की बिल्डिंग में

चल रहे हैं। किराए के भवनों में शिक्षा विभाग की ओर से मरम्मत के लिए बजट नहीं दिया जाता है। इसलिए इन स्कूलों की मरम्मत पिछले तीन-चार साल से नहीं हुई है। राउप्रावि कोरियों का बस नंबर स्कूल जर्जर है। इसके लिए भी शिक्षा विभाग नए भवन की तलाश कर रहा है। वहीं इन स्कूलों के मालिक को जर्जर भवनों की रिपेयरिंग के लिए कहा गया है।

अनूपगढ़ में साढ़े पांच इंच बरसात होने से घरों में दरारें आईं, कई जगह जलभराव

एसडीएम, तहसीलदार और एसएचओ क्षेत्र में सुरक्षा के बंदोबस्त में जुटे

अनूपगढ़, (निसं)। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में रात करीब दो बजे से लगातार तेज बरसात का दौर जारी है। रात से हो रही बरसात के बाद अब तक करीब 140 एमएम (साढ़े पांच इंच) बरसात शहर में हो चुकी है, जिस कारण शहर की गलियों में पानी भर गया है।

बरसात के कारण वार्ड 29 में एक घर में दरार आई और वही गांव 71 जीबी में एक घर की दीवार गिर गई। बाजार में 2 दुकानों के छज्जे भी गिर गए। एसडीएम सुरेश राव, तहसीलदार श्रीवर्धन शर्मा और एसएचओ ईश्वर जांगिड़ सुबह से ही

- बरसात के कारण वार्ड 29 में एक घर मे दरार आई और गांव 71 जीबी में एक घर की दीवार गिर गई

क्षेत्र में सुरक्षा के बंदोबस्त में जुटे हुए हैं। एसएचओ ईश्वर जांगिड़ के द्वारा आमजन से घरों में रहने की अपील की जा रही है। एसडीएम सुरेश राव ने आमजन से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर के प्राचीन गढ़ की एक बुजुर्ग भरभराकर गिर गई। सारा मलबा सड़क पर आ गया। मिर्ज़ा मार्केट में दो दुकानों के छज्जे गिर गए। 33 ए के पास के ए वितरिका में कटाव आ गया। स्थिति यह है कि वार्ड

नंबर 11 में एक खाली प्लाट की दीवारें ढह गई तो वहीं वार्ड नंबर 29 में एक घर के कमरों में दरारें आ गईं तथा छत से पानी टपकने लगा। इस पर वार्ड नंबर 29 के पार्षद मुराद खान ने तुरंत घर खाली करवाकर मकान मालिक के परिवार को अन्य जगहों पर शिफ्ट किया।

मुрад खान ने बताया कि पुत्र खान पुत्र बप्पा खान निवासी वार्ड नंबर 29 अपने परिवार के साथ दो कमरों

के मकान में रहता है। अत्यधिक बरसात होने के कारण उसके मकान में दरारें आ गई हैं जिस कारण एक बार के लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है।

शहर में लगातार हो रही बरसात के बाद पुलिस थाना रोड, गौरव पथ, वेयरहाउस रोड, प्रेम नगर, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 21 सहित विभिन्न वार्डों की गलियों में पानी गया है। नगर पालिका प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है।

कृषि विभाग के सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) जसवंत सिंह

बराड़ ने बताया कि इतनी बारिश धान की फसल को छोड़कर सभी फसलों के लिए अब नुकसानदायक है। रात करीब एक बजे से लगातार हो रही बरसात के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए स्कूलों में ऑनबाइडिंग में आज का अवकाश घोषित किया है। इस बीच स्कूल स्टाफ स्कूल में मौजूद रहेगा। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ द्वारा भी शहरवासियों से अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले तथा सुरक्षित स्थान पर ही रहे।

सवाई माधोपुर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न

प्रशासन ने भारी बारिश से प्रभावित नागरिकों को राहत सामग्री पहुंचाई

सवाई माधोपुर, (निसं)। हाल ही में सवाई माधोपुर शहर में हुई भारी वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आमजन के दैनिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। जिला कलेक्टर काना राम के निर्देशानुसार नगर परिषद सवाई माधोपुर द्वारा प्रभावित नागरिकों को हरासंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

नगर परिषद आयुक्त नरसी मोघाने ने जानकारी देते हुए बताया कि पुणे शहर की कई कॉलोनिंगों-जैसे अंसारी मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, ब्रह्मपुरी, कुम्हार मोहल्ला, रैगर

- भोजन, पेयजल एवं सफाई व्यवस्था के लिए विशेष टीमें तैनात, कंट्रोल रूम स्थापित

मोहल्ला एवं गुरुद्वारे के पास में जलभराव के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए नगर परिषद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में प्रातः एवं सायं काल जल टैकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही, आज नगर परिषद की टीम एवं

पार्षदों के सहयोग से उक्त क्षेत्रों में लगभग 1000 भोजन पैकेटों का वितरण किया गया। आयुक्त ने बताया कि सभी प्रभावित बस्तियों में सफाई व्यवस्था के लिए सफाईकर्मियों की विशेष टीम लगाई गई है, जो लगातार सफाई कार्य में जुटी हुई है। नगर परिषद द्वारा यह राहत कार्य आगामी दिनों में भी सतत रूप से जारी रखा जाएगा। साथ ही, आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को राहत से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो, तो वह नगर परिषद के कंट्रोल रूम पर संपर्क करें।

तालाब के पानी में बहे बालक का शव पाइप में फंसा मिला

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा

टोंक, (निसं)। टोडारायसिंह उपखण्ड क्षेत्र के गोलेड़ा गांव के तालाब के ओवरफ्लो पानी की रफट पर साथियों के साथ नहाते समय बहे 13 वर्षीय बालक का शव नौ घंटे बाद गुरुवार रात को घटनास्थल से कुछ दूरी पर छोटी पुलिया के नीचे सीमेंट के पाइप में फंसा मिला। रेस्क्यू कर रही एसडीआरएफ की टीम ने शव पुलिस को सौंप दिया, बाद में पुलिस ने शुक्रवार को बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया।

टोडारायसिंह तहसीलदार राहुल पारीक ने बताया कि गोलेड़ा निवासी अर्पित शर्मा पुत्र दौलत शर्मा जो

गुरुवार दोपहर को गांव के तालाब की चल रही चादर के पानी में नहा रहा था, जहां उसका सन्तुलन बिगड़ने से वह पानी के बहाव में बह गया। बाद में उसके साथ नहा रहे बच्चों के चिल्लाने पर ग्रामीण वहां आये तथा बच्चों के बताए अनुसार उसकी तलाश करना शुरू की। बाद में पुलिस और उसके परिजनों को भी सूचना दी। कुछ देर बाद परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर ही एसडीआरएफ की टीम बुलाकर बालक की तलाश शुरू की, टीम ने बीती रात को ही घटना स्थल के पास नाले की पुलिया के नीचे पाइप में फंसे बच्चे के शव को निकाला।

No. — 1969-71

Date— 31.07.2025

Notice Inviting Tender (E-12)

N.I.T. is invited on behalf of Governor of Rajasthan by Municipal Council Dholpur for Pani nikasi work from Registered Contractor the amount of work is 28 lacs and UBN No. are has under.
UBN No-DLB2526GLOB13135
For detail visit www.sppp.rajjasthan.gov.in & www.eproc.rajjasthan.gov.in

Commissioner
Municipal Council Dholpur

Raj.Samwad/C/25/7378

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ०४, मीनार, अजमेर- 313001(राज.))
फोन नम्बर: (0294)2428768/2428763-67, फोन: (0294)2428768, 2428739

ई-निविदा सूचना
दिनांक :- 01/08/2025

निविदा संख्या एवं दिनांक

कार्य का विवरण

ई-निविदा संख्या 06 / 2025-26
UBN No. MML2526SLRC00072

GSFC के बड़ोदर स्थित प्लांट से ग्रामकोटडा खदान, उदयपुर तक फास्फोरिक्स एक्सिड की आपूर्ति हेतु। अनुमानित मात्रा — 2000 MT, घरोहर राशि (रु. में) 48,000 /—, निविदा प्रपत्र मूल्य (रु. में) 1180 /—

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rsmm.com, www.sppp.rajjasthan.gov.in, www.eproc.rajjasthan.gov.in अथवा प्रभोक्ता (एएमए) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।

जल संचार/सी/25/7336

जल संचालनक (का.एल.एन.)

Office of the Medical Superintendent
RUHS Hospital of Medical Sciences, Jaipur
Sector-11, Kumbha Mang, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur. 302033(Raj.)
फ़ोन: 0141-2795577, Email: suptd.hms@ruhsraj.org, ruhs@hms@ruhsraj.org

Notice Inviting e-Bids
Date: 31/07/2025

Single Stage Two envelope Online bids (e-bids) are invited up to 02.00 pm of 28-08-2025 for Supply and Installation of Various Equipment/Items at Dept. of Ophthalmology, RUHS Hospital of Medical Sciences, Jaipur. (Total Est. Cost Rs. 6,17,00,000.00). Details may be seen in the Bidding Documents at the Website sppp.raj.nic.in, or eproc.rajjasthan.gov.in. UBN : CMS2526GLOB00064-68, 71-72, 75-77, CMS2526GSOB00069-70, 73-74

Medical Superintendent,
Raj.Samwad/C/25/7349

RUHS Hospital of Medical Sciences, Jaipur

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
दाउनहॉल सिक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष सं. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट www.udaiapurmc.com
क्रमांक :- निविदा / 2025-26 / ई-18 दिनांक :- 29.07.2025

(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 18/ 2025-26

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्य हेतु कुल राशि रु0 27.72 लाख के कुल 02 कार्यों हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.sppp.rajjasthan.gov.in एवं ई-टेंडरिंग के माध्यम से संबंधित अन्य सम्पन्न विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajjasthan.gov.in, www.sppp.rajjasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं। UBN No. UNP2526WSOB00061
राज.संवाद/सी/25/7299 अधीक्षक अभियन्ता, नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेडिफिक कॉलेज परिसर, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2851464)

क्रमांक— 11336 दिनांक— 31.07.2025

निविदा सूचना
UB N. DLB2526SSOB13182

नगर निगम जोधपुर दक्षिण में दस बुड चीपर धी कीलर मशीन आपूर्ति करने हेतु विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता/रजिस्टर्ड फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी www.isg.rajjasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
आयुक्त
राज.संवाद/सी/25/7316 नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नापासर (बीकानेर)
E-mail:- eeonagarpalikannaapasar@gmail.com
क्रमांक:-न.पा.पा./निर्माण / 2025-26 / 709 दिनांक 28.07.2025

ई- निविदा-सूचना संख 17/निर्माण/2025-26

नगर पालिका नापासर की ओर से विभिन्न कार्यों (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अतिरिक्त को विभागों में "ऐपेंड", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं नगर निगम में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.SPPPRaj.nic.in से व <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। निविदा की कुल लागत 17.90 लाख UBN Number :-DLB2526WSOB13070
राज.संवाद/सी/25/7334 अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-मण्डरायल
क्रमांक-360-375 दिनांक-18.07.2025

ई-निविदा सूचना संख्या-05/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्यो के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों ए. ए. डी, सी व डी श्रेणी एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि के पंजीकृत संवेदकों को कि राज्य सरकार के ए व ए श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदाओं से संबंधित विवरण वेबसाइट eproc.rajjasthan.gov.in & www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। NIB CODE : PWD2526A02074, UBN NO. (1) PWD2526WSOB07484 (2) PWD2526WSOB07488, (3) PWD2526WSOB07490
(समय सिंह मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड मण्डरायल

DIPR/C/10365/2025

महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर एक विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 27 वर्षीय हुकुम सिंह है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरवरी 2025 में आरोपी ने

- फाइनैस कंपनी का अफसर बनकर रेप किया था

खुद को फाइनैस कंपनी में अधिकारी बताते हुए पीड़िता से संपर्क किया और उसे लोन दिलवाने का झांसा दिया। पीड़िता ने भी भरोसा कर लिया। इसके बाद महिला आरोपी के जाल में फंसी गई। अधिक पैसा लोन दिलाने का झांसा देकर महिला से रेप किया। जब लोन नहीं मिला तो घटना के बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर एनईबी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करते ही आरोपी की तलाश शुरू की। अब उसे अरेस्ट कर लिया। रेप व लोन का झांसा दिलाने से जुड़े सबूत भी पुलिस ने जुटाए हैं। इस मामले में गहनता से जांच हो रही है।

थाना प्रभारी ने मामले की पूरी जानकारी अलवर एसपी को भी दी है। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने गुरुवार को आरोपी हुकुम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, भंवर कलां गेट के जर्जर कमरों को ध्वस्त किया।

भीलवाड़ा, (निसं)। झालावाड़ जिले में हाल ही में एक स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। सरकार के निर्देशानुसार राज्य के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय स्कूलों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है ताकि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

इसी क्रम में सोमवार को जहाजपुर उपखंड अधिकारी राजकेश मोघाने ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, भंवर कलां गेट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कुछ कक्षों की हालत अत्यंत जर्जर पाई गई, जिस पर तत्काल प्रभाव से उन कमरों को बंद करने तथा अत्यधिक क्षतिग्रस्त कक्षों को गिराने के आदेश दिए गए थे। शुक्रवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विद्यालय के जर्जर

- एसडीएम की सूझबूझ से समय रहते बची बड़ी दुर्घटना, छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त
- तोड़े गए कक्षों की हालत देखकर यह स्पष्ट हुआ कि वे पूरी तरह मिट्टी और पत्थर से निर्मित थे और बरसात के पानी से दीवारें गीली हो चुकी थीं

कक्षों पर बुलडोजर चलवाया। तोड़े गए कक्षों की हालत देखकर यह स्पष्ट हुआ कि वे पूरी तरह मिट्टी और पत्थर से निर्मित थे और बरसात के पानी के कारण उनकी दीवारें पूरी तरह गीली हो चुकी थीं। समय रहते यदि इन्हें नहीं गिराया जाता, तो किसी भी समय दीवारें या छत गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। विद्यालय में शिक्षात छात्रों एवं स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह

हिरण का शिकार करने वाला गिरफ्तार

बीकानेर, (निसं)। वन विभाग की टीम ने 27 जुलाई की शाम को कानासर की रोही में गोली मारकर दो हिरणों का शिकार करने के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सात साल पहले बंदरासर की रोही में दो हिरण और खरगोश का शिकार करने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ में कानासर की रोही में शिकार करने वाले नामजद हो गए।

वन विभाग के रेंजर महावीर रहिल ने बताया कि रविबार की शाम को कानासर की रोही में दो चिकंकार हिरणों का गोली मारकर शिकार किया गया था। मौके से मृत हिरण बरामद हुए, लेकिन शिकारी फरार हो गए थे। पूर्व में 24 मई, 18 को 19 जेएमडी बंदरासर की रोही में दो मादा हिरण और खरगोश का शिकार किया गया था जिसमें 10 अभियुक्त नामजद थे। तीन को गिरफ्तार किया गया और सात फरार थे। उनमें से बंदरासर कावनी निवासी लखाराम को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उसने कानासर की रोही में शिकार करने वाले जसवंत का नाम भी उगल दिया। वन विभाग की टीम ने जसवंत को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। उसके साथी की तलाश की जा रही है। पुराने मामले में गिरफ्तार लखाराम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पैथर ने मवेशियों का शिकार किया मसूदा, (निसं)। मसूदा क्षेत्र के उत्तमी ग्राम में एक बार फिर पैथर ने मवेशियों का शिकार किया। करीब एक दर्जन मवेशियों को निवाला बना दिया। बीती रात कस्बे वासियों द्वारा एक खेत में पैथर के शावक देखे गए, जिसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। मौके पर अधिकारी द्वारा शावक की फोटो देखकर जंगली बिल्ली के बच्चे बता कर इतिश्री कर ली, लेकिन जब रात को उन्हीं शावक को मादा द्वारा मवेशियों को शिकार किया गया तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। सरपंच प्रतिनिधि लाला काठार ने बताया कि इन शावकों की सूचना विभाग को रात को ही दे दी गई थी।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल फुलेरा, जिला-जयपुर
क्रमांक / न.पा.फु. / नि.शा / 2025-26 / 992 दिनांक : 31.07.2025

:- निविदा सूचना :-

नगर पालिका फुलेरा की ओर से निम्नानुसार विभिन्न कार्य हेतु करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। उक्त निविदा सूचना से सम्बन्धित समस्त शर्तें एवं विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajjasthan.gov.in> पर NIB CODE- DLB2526A4140 द्वारा देखा जा सकती है। तथा उक्त कार्यों के UBN Number — DLB2526WSOB13140, DLB2526WSOB13141 है।
राज.संवाद/सी/25/7347 अधिशाषी अधिकारी

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
PWD DIVISION DHOLPUR**

File No. 1056-67 Date: 22.07.2025

Notice Inviting Bid
NOB CODE: PWD2526A2158 and UBN is: PWD2526WSOB07801
NOB CODE: PWD2526A2158 and UBN is: PWD2526WSOB07803
Bids For NIT No. 03/2025-26 Misse. Work of PWD Division Dholpur of subject matter(s) of Procurement are Invited from interested bidders date 24.07.2025 11.00 AM to Date 04.08.2025 upto 6.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal <http://eproc.rajjasthan.gov.in> <http://sppp.raj.nic.in> of the state. and PWD Division Dhholpur. The approximate value of the procurement is Rs. 60.00 Lacs.
(Nareesh Chand Meena)
Executive Engineer
PWD Division Dholpur

DIPR/C/10609/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चॅवली परियोजना नहर खण्ड, झालावाड़
क्रमांक-निविदा/2025-26/1372-85 दिनांक- 24.07.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 05/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा नवीन पंजीकरण नियमों के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से Tree Plantation in mission Hariyalo Rajasthan कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित कुल लागत राशि रु. 66.90 लाख है। निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> की वेबसाइट से डाउनलोड एवं अपलोड की जावेगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट <http://www.waterresources.rajjasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा दिनांक 25.07.2025 प्रात 9.30 बजे से दिनांक 04.08.2025 प्रात 06.00 बजे तक से <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> से Upload की जा सकती है/देखी जा सकती है। NIB CODE: WRD2526A02078, UBN is WRD: WRD2526WSOB00753
(वीरेंद्र सिंह) अधिशाषी अभियन्ता
चॅवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड़

DIPR/C/10776/2025

कार्यालय नगर पालिका, बालेसर सत्ता (जोधपुर) राज.
Municipal Board, Balesar Satta (Jodhpur) Rajasthan e-mail:- combalesar2022@gmail.com
क्रमांक:- न.पा.बालेसर/सी/स्टोर / 2025-26 / 648 दिनांक:- 24.07.2025

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना (2025-26)
(NIB NO.- DLB2526A3901)

नगरपालिका बालेसर सत्ता की ओर से नगरपालिका बालेसर सत्ता एवं राजकीय विभाग में निम्नानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया अनुसार सफाई श्रमिक व स्वास्थ्य निरीक्षक आपूर्ति कार्य की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत 24.90 लाख रु. की निविदा ऑनलाईन जारी की दिनांक एवं निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।
प्रशासक
नगरपालिका बालेसर सत्ता
राज.संवाद/सी/25/7328

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No.- F-2(01)Actt/Contract/2025-26/111 - 113 Date: 30/07/2025

ई-निविदा सूचना संख्या : 29/2025-26

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निर्माणाधीन कार्य मय फिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यों की कुल लागत	रुपये 1562.17 लाख (02 करोड़)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें /	01.08.2025 को प्रातः 10.00 बजे से
अपलोड करने की अवधि	28.08.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing	01.08.2025 को प्रातः 10.00 बजे से
Fee जमा करने की तिथि	28.08.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	29.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे (तकनीकी बिड)

विस्तृत विवरण वेबसाइट urban.rajjasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No.:- ITU2526WLOB00196, ITU2526WLOB00197
अधिशायी अभियन्ता - प्रवन्
दल.संवाद/सी/25/7342 उदयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत
क्रमांक-1244 दिनांक-24.07.2025

Notice Inviting Bid: 16-26/2025-26

Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 05.08.2025 at 14.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajjasthan.gov.in & "http://eproc.rajjasthan.gov.in" of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 300.70 lacs and maximum value of single work in this procurement is 29.92 lac.

NIT NO.	16	17	18	19
UBN NO.	PHE2526WSOB04930	PHE2526WSOB04931	PHE2526WSOB04934	PHE2526WSOB04934
NIT NO.	20	21	22	23
	PHE2526WSOB04935	PHE2526WSOB04936	PHE2526WSOB04937	PHE2526WSOB04938
NIT NO.	24	24	26	
	PHE2526WSOB04939	PHE2526WSOB04940	PHE2526WSOB04941	

जल सीमेंट है, इसकी बरत करें। (चर्नक कुमवार)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड कोलायत

DIPR/C/10553/2025

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर
क्रमांक-प.2/आ.मि./कॉटन बेंडेज उपा. /2025-26/ दिनांक-21.07.2025

ई-बोली विनिर्दिष्ट वर्ष 2025-26

(विभागीय चिकित्सालय/औषधालयों हेतु कॉटन, बेंडेज का क्रय)
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभागीय चिकित्सालय/औषधालयों के उपयोगार्थ कॉटन, बेंडेज की विभागीय रसायनशाला पर आपूर्ति हेतु राजस्थान में स्थित पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 7 की शर्तों (1) के अंतर्गत अधिभूत इकायों वाले इच्छुक बोलीदाताओं से क्रय की कुल अनुमानित राशि रु. 150.00 लाख रु. ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कॉटन, बेंडेज के क्रय हेतु फॉर्म डाउनलोड प्रारंभ करने की दिनांक 21.07.2025 सायं 6.00 बजे से एवं स्वीकार करने की अंतिम तिथि 13.08.2025 प्रातः 11.00 बजे रखी गई है।
बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाइट <https://eproc.rajjasthan.gov.in>, <https://dipr.rajjasthan.gov.in>, <https://sppp.rajjasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
Job wise Cotton, Bendez UBN NO.- AYU2526GLOB00261
DIPR/C/10607/2025 निदेशक

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय, धौलपुर
E-mail:- ee2wrddlp@gmail.com, Add- Irrigation Colony G.T.
Road Dholpur-328001

क्रमांक-निविदा/2025-26/782 दिनांक-25.07.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा नवीन पंजीकरण नियमों के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से Mission Hariyalo Rajasthan के अंतर्गत Plantation work हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित कुल लागत राशि रु. 64.12 लाख है। निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> की वेबसाइट से डाउनलोड एवं अपलोड की जावेगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट <http://www.waterresources.rajjasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा दिनांक 28.07.2025 प्रात 9.30 बजे से दिनांक 05.08.2025 प्रात 05.00 बजे तक से <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> से Upload की जा सकती है/देखी जा सकती है। NIB CODE : WRD2526A02090, UBN is WRD : WRD2526WSOB00773

आवासन मंत्रालय के सचिव ने वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का निरीक्षण किया

सचिव श्रीनिवास ने लांगड़ियावास में स्थित प्लांट का दौरा किया

जयपुर। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव कातिकियाला श्रीनिवास ने शुक्रवार को जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के ग्राम लांगड़ियावास में स्थित ठोस अपशिष्ट आधारित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का दौरा किया। यह प्लांट राजस्थान सरकार की स्वच्छ भारत



सचिव कातिकियाला श्रीनिवास (बीच में) ने जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के ग्राम लांगड़ियावास में स्थित ठोस अपशिष्ट आधारित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का दौरा किया।

■ श्रीनिवास ने प्लांट प्रमुख से प्लांट की कार्य प्रणाली, उपयोग लाई जा रही तकनीकों, अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया,पर्यावरणीय लाभों पर विस्तृत जानकारी ली

मिशन (शहरी) के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है, जिसे ज़िंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (जयपुर) लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल से संचालित किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के निदेशक जुझर प्रतीक चंद्रशेखर एवं आयुक्त, नगर निगम जयपुर

(हेरिटेज) डॉ. निधि पटेल ने श्रीनिवास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य शासन विभाग व निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता भी उपस्थित रहे।

श्रीनिवास ने प्लांट प्रमुख से प्लांट की कार्यप्रणाली, उपयोग लाई जा रही नवीनतम तकनीकों, अपशिष्ट से ऊर्जा

निर्माण प्रक्रिया एवं पर्यावरणीय लाभों पर विस्तृत जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण प्लांट का भ्रमण कर इसकी कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

इस अवसर पर श्रीनिवास ने स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम, जयपुर एवं ज़िंदल समूह के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह प्लांट इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलकर शहरी चुनौतियों का सतत समाधान

प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह संयंत्र न केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक है बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम योगदान दे रहा है।

फरवरी, 2025 से संचालित इस प्लांट में प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे का प्रसंस्करण कर प्रतिदिन 12 मेगावाट-घंटा का विद्युत उत्पादन किया जाता है जिस से लगभग 2.5 करोड़ रूपए की आय नगर निगम को होती है।

जन जागरूकता अभियान में यातायात नियमों की जानकारी दी

जयपुर। राजधानी जयपुर में पुलिस उपायुक्त यातायात सुमित मेहरडा के निदेशन में यातायात पुलिस जयपुर की ओर से यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार करने के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर हर वर्ग तक यातायात जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस कड़ी में शुक्रवार को यातायात शिक्षा टीम द्वारा केपीएस उड़ान स्कूल विद्याधर नगर एवं टीवीबी गर्ल्स पब्लिक

■ पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार एवं उनकी टीम ने विद्यार्थियों एवं बाल वाहिनी वाहन चालकों को यातायात संकेतकों से अवगत कराया

सीनियर सैकण्डरी स्कूल अम्बाबाड़ी पर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें यातायात शिक्षा टीम के पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार एवं उनकी टीम ने विद्यार्थियों एवं बाल वाहिनी वाहन चालकों को यातायात

नशों में वाहन नहीं चलाने आदि के बारे में समझाईश की गई सड़क दुर्घटना के समय अच्छा मददगार बनने तथा मुख्यमंत्री आनुष्मान जीवन रक्षा योजना के बारे में अवगत कराया गया। स्कूलों में ट्रैफिक क्लब बनाकर विद्यार्थियों को ट्रैफिक वालंटियर की तरह भी यातायात का व्यावहारिक प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली की समझ के लिए ट्रैफिक पॉइंट पर यातायात पुलिसकर्मियों के साथ कुछ समय के लिए नियोजन के लिए प्रेरित किया गया।

डॉक्टर से चालीस लाख रुपये की रंगदारी मांगी

जयपुर। करणी विहार थाना इलाके में एक डॉक्टर से चालीस लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। घर के मेन गेट पर धमकी भरा लेटर एक लिफाफे में रखकर फेंका गया। लेटर में लिखा कि ज्यादा होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। इस संबंध में पीड़ित डॉक्टर ने थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस टीम की ओर से मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि करणी विहार के रहने वाले एक डॉक्टर ने मामला दर्ज करवाया है कि वह चित्रकूट इलाके में प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। गत दो दिन पहले रात में अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश उसके घर के बाहर आए और घर के मेन गेट के ऊपर से एक लिफाफे में धमकी भरा लेटर फेंक कर चले गए। अगले दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल रहे थे। मेन गेट के पास उनको लिफाफा पड़ा दिखाई दिया। लिफाफा खोलकर देखने पर उसमें धमकी भरा लेटर मिला। धमकी भरा लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ था कि ज्यादा

■ अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश उसके घर के बाहर आए और घर के मेन गेट के ऊपर से एक लिफाफे में धमकी भरा लेटर फेंक कर चले गए

■ लेटर में लिखा कि ज्यादा होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा

होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप चालीस लाख रुपए दे देना। लेटर के जरिए धमकी देकर चालीस लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पीड़ित डॉक्टर की ओर से धमकी भरा लेटर मिलने के बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस की ओर से मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है। पुलिस टीमों की ओर से पीड़ित डॉक्टर के घर के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है।

अनुसूचित जाति के प्रबुद्धजनों के साथ सामाजिक न्याय मंत्री ने बैठक ली

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री 3अविनाश गहलोल ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के उन्धान के लिए कृत-संकल्पित है। सरकार की मंशा है कि सामाजिक न्याय की सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके।

गहलोल बुधवार को अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध नागरिकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का उन्धान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

■ ‘अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित’

■ गहलोल बुधवार को अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध नागरिकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की

छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने, छात्रावासों के आधुनिकीकरण, अंबेडकर भवनों में पुस्तकालय खोलने, पंचतीर्थ योजना में खासकर युवाओं को शामिल करने, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था बेहतर करने, छात्रावासों की मॉनिटरिंग करने, नए छात्रावास खोलने सहित अन्य विषय संस्थाओं द्वारा उठाए गए।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि विभाग द्वारा

एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर चल रहे धरने के 100 दिन पूरे

जयपुर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर चल रहे धरने को लेकर कहा कि आज धरने को 100 दिन पूरे हो गए मगर सरकार अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील नहीं है,उन्होंने कहा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करवाने तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर उन्होंने बड़ी रैली की व लोक सभा में भी मामला उठाया।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से आज 100 दिन आंदोलन के पूरे होने पर धरने पर बैठे युवाओं तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने भारत के तिरंगे के प्रतीक कलर के गुब्बारे लगाकर सरकार को संदेश दिया कि हम संविधान की भावना का सम्मान करते हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसानों को जारी करेंगे पीएम-किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी (उत्तरप्रदेश) से देशभर के किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। मोदी 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। इस आयोजन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह के जरिए जुड़ेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहेंगे। शर्मा राज्य स्तरीय समारोह में कृषि विभाग की पॉलीकोइस, सीर ऊर्जा पंप संयंत्र, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, तारबंदी और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत लाभार्थी किसानों को अनुदान राशि के प्रतीकात्मक चेक वितरण करेंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने पात्र परिवार और लाभार्थियों से संबंधित प्रश्न लगाया था, जिसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण



दिन भर रुक रुक कर छितराई हुई बारिश का दौर चला। अजमेर रोड पर आई तेज बारिश के बाद लगा लंबा जाम।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में बांसवाड़ा में आयोजित होगा राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह

■ किसानों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए पीएम-किसान जैसी योजना एक मील का पथर है : सांसद मदन राठौड़

राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था। योजना के तहत अब तक 19 किश्तों में 3.69 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है। पहली किश्त में जहां देशभर के 3 करोड़ 16 लाख 21 हजार से अधिक लाभार्थियों के खाते में 6324 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए थे, वहीं 19वीं किश्त के रूप में 10 करोड़ 6 लाख 85 हजार से अधिक लाभार्थियों के खाते में 23500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर सैचुरेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। 2023 में जहां भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना में शामिल किया गया था, इसके बाद नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत लगभग 25 लाख और पात्र किसान परिवारों को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद सितंबर 2024 से विशेष अभियान चलाकर फिर से वंचित पात्र परिवारों को योजना में शामिल करने का प्रयास किया गया।

मरीज को जयपुर लेकर आ रही एंबुलेंस ट्रक में घुसी

जयपुर। कानोता थाना इलाके के जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे-21 पर सांप डसने वाले मरीज को जयपुर लेकर जा रही एंबुलेंस ट्रक में घुस गई। इस हादसे में मरीज और उसकी मां

सार-समाचार

अरशद हुसैन बने इवेंट मैनेजर्स डे के ग्लोबल कन्वीनर



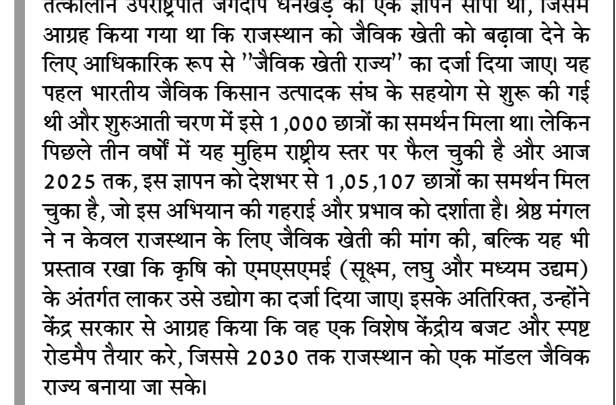
जयपुर। जयपुर के लिए यह गर्व का अवसर है, जब इवेंट गुरु के नाम से इवेंट इंडस्ट्री में प्रसिद्ध इवेंट प्रोफेशनल, अरशद हुसैन को एक बार फिर इवेंट मैनेजर्स डे के ग्लोबल कन्वीनर के रूप में अगले 2 साल के लिए निर्वाचन चुना गया। यह उपलब्धि और भी खास इसलिए है क्योंकि यह पहली बार है जब किसी भारतीय को लगातार दो कार्यकाल के लिए यह वैश्विक जिम्मेदारी सौंपी गई है और

वह भी गुलाबी नगर जयपुर से। हुसैन ने जब नेतृत्व संभाला था तब इवेंट मैनेजर्स डे का आयोजन सिर्फ 32 देशों तक सीमित था और अब इसका दायरा बढ़कर करीब 70 देशों तक पहुंच चुका है। इस तरह जयपुर से जुड़े एक प्रोफेशनल का नाम आज वैश्विक मंच पर पूरे सम्मान के साथ लिया जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय कमेटी में 11 देशों के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने सर्वसम्मति से अरशद को पुनः कन्वीनर चुना। इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस निर्णय को न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि माना, बल्कि इसे राजस्थान की इवेंट मैनेजमेंट क्षमताओं की वैश्विक पहचान के रूप में देखा जा रहा है। यह इवेंट इंडस्ट्री के लिए एक प्रेरणादायक पल है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने का हौसला देगा।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आज

जयपुर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती की अध्यक्षता में शनिवार को प्रातः 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर में प्रदेश स्तरीय “डॉ. कलाम स्टार्टअप यूथ अवॉर्ड 2.0” प्रदेश बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, स्थाई आमंत्रित सदस्य, जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री उपस्थित रहेंगे बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सम्बोधित करेंगे।

राजस्थान को “जैविक खेती राज्य” घोषित करने की मांग



जयपुर। राजस्थान को “जैविक खेती राज्य” घोषित करने की मांग को लेकर एक छात्र द्वारा शुरू किया गया प्रयास अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। वर्ष 2022 में जयपुर के 13 वर्षीय छात्र श्रेष्ठ मंगल ने भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आग्रह किया गया था कि राजस्थान को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक रूप से “जैविक खेती राज्य” का दर्जा दिया जाए। यह पहल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के सहयोग से शुरू की गई थी और शुरूआती चरण में इसे 1,000 छात्रों का समर्थन मिला था। लेकिन पिछले तीन वर्षों में यह मुहिम राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है और आज 2025 तक, इस ज्ञापन को देशभर से 1,05,107 छात्रों का समर्थन मिल चुका है, जो इस अभियान की गहराई और प्रभाव को दर्शाता है। श्रेष्ठ मंगल ने न केवल राजस्थान के लिए जैविक खेती की मांग की, बल्कि यह भी प्रस्ताव रखा कि कृषि को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के अंतर्गत लाकर उसे उद्योग का दर्जा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह एक विशेष केंद्रीय बजट और स्पष्ट रोडमैप तैयार करे, जिससे 2030 तक राजस्थान को एक मॉडल जैविक राज्य बनाया जा सके।

संसदीय कार्य मंत्री ने राजकीय महाविद्यालय झंवर के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया

जोधपुर / जयपुर । संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर जिले के झंवर में राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक



जोगाराम पटेल (बीच में) ने शुक्रवार को झंवर में राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

■ बजट घोषणाओं की समयबद्ध धरातल पर हो रही क्रियान्विति - संसदीय कार्य मंत्री

■ गत सत्र में ही महाविद्यालय शुरू हो गया और भवन निर्माण कार्य 4.5 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है

क्रियान्विति सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा दूरस्थ क्षेत्रों में महाविद्यालय खुलने से प्रदेश भर की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के खुलेंगे। पटेल ने कहा गत बजट में झंवर में महाविद्यालय की घोषणा हुई थी, गत सत्र में ही महाविद्यालय शुरू

हो गया और भवन निर्माण कार्य 4.5 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। उन्होंने कहा इस बजट में केरु में भी नवीन महाविद्यालय की सीगात मिली है।

बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समयावधि में कार्य पूर्ण करें:-पटेल

ने राजस्थान शहरी पेयजल सिल्वरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड (रुडसिस्को) के सहायक अभियंता राजेश व्यास को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा भवन निर्माण कार्य को बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समयावधि पूर्ण करें।

युवाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम है युवा संसद : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधान सभा के सदन में तेरह राज्यों के 168 युवा देश की सुरक्षा से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद करेंगे। विधान सभा में शनिवार को प्रातः 10 बजे इस एक दिवसीय युवा संसद का राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष देवनानी शुभारम्भ करेंगे। समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और संघ के सचिव संदीप शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित इस युवा संसद का राजस्थान विधान सभा के यू-ट्यूब चैनल पर सजीव प्रसारण किया जायेगा।

देवनानी ने बताया कि देश के दस राज्यों राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरात और तीन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ व नई दिल्ली के 55 विधायकों के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के चयनित 168 युवा छात्र-छात्राएं आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करवाने के प्रयासों पर संवाद कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के हल का मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे।

विधान सभा सदन में 56 युवा

■ विधानसभा में युवा संसद, राजस्थान विधान सभा में तेरह राज्यों के 168 युवा जुटेंगे

■ समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और संघ के सचिव संदीप शर्मा भी मौजूद रहेंगे

■ विधान सभा सदन में 56 युवा निर्धारित समय में अपनी बात रखेंगे

निर्धारित समय में अपनी बात रखेंगे। देवनानी ने बताया कि युवा संसद एक ऐसा मंच है जो छात्रों को संसदीय प्रक्रिया और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के बारे में सिखाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह छात्रों को राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर बहस करने, अपने विचार व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को वर्तमान ट्रैफिक स्थिति को सुगम एवं सुचारु बनाने के निर्देश दिए।

जयपुर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री करने की योजना बनायें

मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर बैठक में निर्देश दिये

जयपुर, 1 अगस्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था को तुरंत सुगम एवं सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात संचालन हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत दीर्घकालीन कार्ययोजना के लिए गृह एवं यातायात विभाग, जेडीए, शहरी विकास एवं आवासन व स्वायत्त शासन विभाग मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर

- मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों व आमजन से सुझाव लेकर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था विकसित करें। मानसून के बाद हीरापुरा बस टर्मिनल से बसों का संचालन किया जाए।**

शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस एवं यातायात के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को जागरूक करते हुए ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में जयपुर शहर में वाहनों के सुगम संचालन

और जाम से राहत के लिए व्यापारियों एवं आमजन से सुझाव लेकर व्यवस्तम मार्गों पर वन वे ट्रैफिक संचालन की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के चिन्हित आँटी और बस स्टैण्ड के स्थानांतरण को शीघ्र लागू किया जाए। इसी क्रम में हीरापुरा

बस टर्मिनल से मानसून के तुरंत बाद बसों का संचालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों की सख्त पालना कराने और उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रमुख चौराहों को चिन्हित कर सिग्नल फ्री ट्रैफिक संचालन की कार्ययोजना बनायीं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ट्रंप को जवाब -भारत अमेरिका से एफ-3 5 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा

वाइट हाउस में फरवरी 2025 में ट्रंप ने मोदी से ये विमान खरीदने की पेशकश की थी

नई दिल्ली, 1 अगस्ता। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा जारी है। हालांकि, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2५ फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इस बीच भारत की ओर से भी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका के एफ-३५ लड़ाकू विमान को खरीदने से इनकार कर दिया है।

ब्लूमबर्ग ने अधिकारियों के हवाले से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स की खरीद में तेजी लाने पर विचार करने के बावजूद, भारत सरकार द्वारा अमेरिका से एंटीशनल डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने की संभावना नहीं है। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका को सूचित कर दिया है कि वह एफ-३५ स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने का इच्छुक नहीं है।

‘चाहे आप रिटायर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना जारी रखने का आग्रह करता है। इन बयानों को नज़अंदाज करना ही सबसे अच्छा है।”
मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे भारत विशेषी बयान दे रहे हैं, जो उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नहीं करना चाहिए।

राहुल गांधी अगले सप्ताह कर्नाटक के अपने दौरे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जहाँ उनसे चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के संबंध में कुछ विस्फोटक खुलासे की उम्मीद

है। इस सब का निशाना है बिहार में मतदाता सुविचों का पुनरीक्षण और वो तरीका, जिससे बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों मतदाताओं को सूचियों से हटा दिया गया है।

विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को इसी सत्र में समाप्त कर देना चाहता है, ताकि चुनाव आयोग परिचम बंगाल जैसे अन्य चुनाव वाले राज्यों में भी ऐसा ही न करे। लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल की स्पष्ट और सटीक बात, और नरेन्द्र मोदी की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आक्रामकता, मोदी और उनकी टीम के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों की उपस्थिति का विरोध

नई दिल्ली, 1 अगस्ता। विपक्ष ने राज्यसभा मेंविरोध प्रदर्शनों के दौरान सदन के बीचोंबीच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों को भेजे जाने का आरोप लगाते हुए इसका कड़ा विरोध किया है और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उउ सभापति हरवंश को पत्र लिख कर यह मुद्दा उठाया है। खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की ओर से लिखे पत्र में कहा है कि कल और आज सदन में सदस्य जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान दिखा कि सीआईएसएफ के कर्मी अंदर बीचोंबीच आ कर खड़े हो गये थे।

भी तरह के मुआवजे के हकदार नहीं है और उन्होंने समय-समय पर घोखाघड़ी और तथ्य छुपाकर भूमि पर मालिकाना हक पाने की कोशिश करी है और जागीरदारी अधिनियम के हटने और राजस्थान टनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व एक नाबालिग जागीरदार की जमीन हथियाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि जो पट्टा उनके द्वारा पेश करा गया वह भी कानूनी तौर पर त्रुटियों से भरा हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि टी.एन. साहनी कभी भी यह साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने उक्त भूमि पर किसान बनकर हल चलाया। अदालत ने कहा कि 1९९० में दिये गये आदेश से जाहिर होता है कि अदालत ने भी त्रिलोकीनाथ द्वारा दिये गये तथ्यों को ‘फैस वैल्यू’ पर ही सही मान लिया और कभी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी को अदालत में नहीं बुलाया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी त्रिलोकीनाथ की नहीं थी। इसके साथ ही अदालत ने त्रिलोकीनाथ के वंशजों द्वारा मुआवजे की करोड़ों की मांग को भी खारिज कर दिया।

‘एसटी वर्ग की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पैदा करता हो। अनुच्छेद 1४ महिलाओं के लिए समानता की गारंटी देता है।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता लखन शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता अपने पिता की इकलौती संतान है। उसने अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए उपखंड अधिकारी के समक्ष वाद दायर किया था। इस दौरान, प्रतिवादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, की धारा २(२) के प्रावधानों के आधार पर सीपीसी के आदेश ७ नियम ११ के तहत अर्जी पेश कर वाद खारिज करने की मांग की। प्रतिवादी ने कहा कि यह अधिनियम एससी वर्ग के सदस्यों पर लागू नहीं

छात्रसंघ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मांगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई टाल दी।
याचिका में बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। वहीं, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत, हर साल छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए। कमेटी की सिफारिश के अनुसार सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव हो चाहिए।

बिहार की पूर्व मतदान सूची में 22 लाख मृत पाये गये

पटना, ०१ अगस्ता। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में चलाये गये विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार पूर्व में सूची में जुड़े २२ लाख मतदाता मृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्त में जानकारी दी गयी कि बीएलओ की सहायता से कराये गये सर्वेक्षण में २२ लाख, ६९ हजार (२.८३ प्रतिशत) मतदाता मृत पाये गये, ३६ लाख, २८ हजार (४.५९ प्रतिशत) मतदाताओं के नाम अन्य स्थानों पर भी पंजीकृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस अभियान के तहत राज्य भर में बीएलओ के माध्यम से कुल सात करोड़, ८९ लाख, ६९ हजार, ८४४ गणना प्रपत्र मुद्रित करा कर संबंधित मतदाताओं के बीच वितरित किये गए थे। इनमें से १६ लाख से अधिक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किये गये।

शाहरुख खान, विक्रांत मैसी व रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार

दिल्ली में ७१ वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा

नयी दिल्ली , ०१ अगस्ता। किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान और अभिनेता विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में शुक्रवार को ७१वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा की गई। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। शाहरुख को उनकी फिल्म जवान और विक्रांत को १२वीं फेल के लिए अवॉर्ड मिला है। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वसेंज नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। फिल्म ‘कटहल’ को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिये चुना गया है।

करण जोहर की ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ को सुपूंग मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित ‘१२वीं फेल’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया, जबकि ‘द केरला स्टोरी’ के लिए सुदीप्तो सेन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवॉर्ड अपने नाम किया।

सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर

ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

उन्हें १७००० करोड़ के लोन फ्रॉड व मनी लॉण्डरिंग के मामले में ५ अगस्त को पूछताछ के लिये बुलाया

- लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है, जब जांच एजेन्सी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।**

करना और यात्रा प्रतिबंध लगाना, यह दर्शाता है कि जांच एजेंसी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अनिल अंबानी के खिलाफ एलओसी जारी करना सामान्य कदम नहीं है। यह तब किया जाता है, जब जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है। या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

इस कदम से सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट जारी हो गया है।

इससे अनिल अंबानी की विदेश यात्राओं पर रोक लग गई है। यह एक साफ संकेत है कि ईडी इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह अनिल अंबानी की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहती है।

अधिकारियों का कहना है कि यह जांच सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और सेबी जैसे अन्य नियामक निकायों की रिपोर्ट पर आधारित है। ईडी की जांच में लीन के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से, २०१७ और २०१९ के बीच यस बैंक की ओर से अंबानी की ग्रुप कंपनियों को दिए गए ३,००० करोड़ रुपये के लोन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने कई अनियमितताओं की बात कही है। इसमें बैंकडेटेड क्रेडिट अप्रुवल, उचित जांच की कमी और विभिन्न ग्रुपों और शेल कंपनियों के फंड का गलत इस्तेमाल शामिल है।

मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार

शाहरुख खान	विक्रांत मैसी	रानी मुखर्जी
		
फिल्म का पुरस्कार दिया गया 'सैम बहादुर' की वैभवाश्र और मेकअप के	की प्रेम कहानी (हिंदी) के लिये कोरियोग्राफर वैभवी मंचेट को मिला।	एंठ ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ वृत्तिचित्र का पुरस्कार मिला । विजयराघवन और मुधुपेट्टई सोमू भास्कर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तथा उर्वशी और जानकी बोडीवाला ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। हनु-मान को (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार गिफ्ट द स्कैवेंजर को मिला।

- शाहरुख खान को फिल्म “जवान” तथा मैसी को “१२ वीं फेल” के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। रानी मुखर्जी को “मिसेज चटर्जी वसेंज नॉर्वे” के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है।**

लिए भी सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार रॉकी और रॉनी प्लॉवरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार; गॉड बल्वर

कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप का दोषी माना

बैंगलुरु की विशेष अदालत में शनिवार को सजा सुनाई जायेगी

मैसूरु, १ अगस्ता।बैंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है। यह मामला हासन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहला रेप केस था। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह केस काफी चर्चा में रहा था। अब इस मामले में सजा का ऐलान शनिवार को होना है। बैंगलुरु की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है। बैंगलुरु स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने १८ जुलाई को दर्शाया को बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी कर

- प्रज्वल रेवन्ना जनतादल (सैक्यूलर) के नेता हैं तथा हासन लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र तथा कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के पुत्र हैं।**

ली थी तथा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा का ऐलान अब शनिवार (२ अगस्त) को होना है। रेवन्ना पिछले साल दर्ज किए गए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं। जब २,००० से अधिक अश्लील वीडियो विलप, जिनमें कथित तौर पर कई महिलाओं के यौन शोषण को दर्शाया गया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुई

‘अन्य देशों को अब अमेरिका की ...

अधिक शुल्क वाली श्रेणियों में रखा गया है। क्लिक्स चडियां पर अमेरिका में प्रवेश के लिए ३९ प्रतिशत का शुल्क लगेगा। एक ब्रिटिश-आधारित कंपनी, जो यूके और यूएसए में क्लिक्स चडियां का यह व्यापार संभालती है, का कहना है कि इससे मांग में कमी आएगी।

भारत को अपेक्षाकृत उच्च शुल्क श्रेणी (२५ प्रतिशत) में रखा गया है। तथापि, यदि रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए डॉनल्ट ट्रम्प के दंडात्मक शुल्क भी साथ-साथ शुरू होते हैं, तो भारत को अमेरिकी बाजारों से बाहर निकाला जा सकता है।

(भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात, भारत इन वस्तुओं के सबसे बड़े सप्लायरों में एक है) पर अब १० प्रतिशत के बजाय २५ प्रतिशत का शुल्क लगेगा। ताइवान, जो दूसरा प्रमुख निर्यातक है, पर थोड़ी कम दर, यानी २० प्रतिशत का शुल्क लगेगा। भारत से कर्कड़ों, जूतों और एक्सेसरीज के निर्यात पर भी भारत के लिए निर्धारित २५ प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

शुल्क के वास्तव में प्रभावी होने से पहले एक छोटी सी मोहलत अभी

उपलब्ध है।अभी और अक्टूबर के बीच की गई सभी वर्तमान शिपमेंट को नए शुल्कों से छूट मिलेगी। हालांकि, यह एक छोटी सी मोहलत है, क्योंकि इन शिपमेंट को बहुत पहले से बुक किया जाता है, इसलिए इतनी कम अवधि में इनमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता।

कई देशों ने अब राहत और संतोष की भावना व्यक्त है कि घोषित शुल्क कम से कम पेशानी वाले हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश पर २० प्रतिशत का शुल्क लगाया जाएगा, जिसे वह एक जीत मानता है, क्योंकि पहले ४१ प्रतिशत की कहीं अधिक दर घोषित की गई थी। शुल्क यह इस देश को इंडोनेशिया, पाकिस्तान या वियतनाम जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के साथ एक सापेक्ष समानता पर रखता है। शुल्क का अंतिम प्रभाव संतुलित होगा। क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है तथा निर्यातक, मांग पर शुल्क के प्रभाव की भरपाई के लिए अप शुल्क अंतिम कीमत कम करने का विकल्प चुन सकते हैं।

हालांकि इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं,

क्योंकि वर्तमान स्थिति में भी, लाभ इतना बड़ा नहीं है कि कोई देश बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए शुल्क की सीमा तक कीमतें कम कर सके। बेशक, चीन जैसे कुछ देश हैं, जो कमाई के लिए निर्यात की कीमतों में भारी कमी करने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन यह लंबी अवधि में मदद नहीं करता है, सिवाय इसके कि प्रतिस्पर्धियों की कीमत पर बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखी जाए या बढ़ाई जाए।

सोमवार, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
और कोर्ट के गलियारों में काफी भीड़ होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन दिनों इन स्थानों पर बड़ी संख्या में अदालतों को बहुत पहले से बुक किया जाता है, इसलिए इतनी कम अवधि में दूसरे कोर्ट में जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कई मामलों में, इंटर्न्स बार के सदस्यों द्वारा अनुप्रेष किए जाने पर भी अपनी सीटें खाली नहीं करते हैं, जिससे वकीलों की और असुविधा होती है।”

^[1] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/६३ इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: २३७२६३४, ४१०३३३३-३४, फैक्स: ०१४१-२३७३५१३, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, छत्रपति सिंघाजी मार्ग, कोटा। फोन: २३८६०३१, २३८६०३२,फैक्स:०७४४-२३८६०३३, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: २२००६६०, फैक्स ०१५१-२५२७३७१, उदयपुर कार्यालय: आनंद मेन रोड आनंद, उदयपुर। फोन: २४१३०९२, फैक्स: ०२९४-२४१०१४६, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत घराना, चूंगी नका के पास, अजमेर। फोन: २६२७६१२, फैक्स:०१४५-२६२४६६५ जालौर कार्यालय :- जी १/६३, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर।फोन2२६४२२,2२६४२३, फैक्स: ०२९७३-२२६४२४ हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी १-१०१, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: २३०२००, २३०४००, फैक्स: ०७४६९-२३०६०० सूूर कार्यालय: एच-१५०, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: २५६९००६, २५६९००७, फैक्स: ०१५६२-२५६९००८